सशक्तीकरण का संकल्प

निर्णायक भूमिका में हैं अब महिलाएं

रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखंड

एक चौपाल कितनों को मुखर बना सकती है. इसका उदाहरण हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है. राज्य के संताल परगना इलाके के अलग-अलग हिस्सों में हमारी जन-चौपाल यात्रा आगे बढ़ रही है. करबिंघा से लेकर बिलकंदी तक जहां-जहां गया, कई नये अनुभवों से रू-ब-रू हुआ. कैसे गांव, घर और अपने परिवार के लिए राज्य की महिलाएं अनवरत संघर्ष करती हैं और परिवार की समृद्धि में अपने को झोंक देती हैं. ऐसी ही महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हमने उज्ज्वला योजना से लेकर एक रुपये में महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री के लिए अतिमहत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. शीघ्र ही सुकन्या योजना हमारी बेटियों के भविष्य को नयी आशाओं से भर देगी. इस योजना के तहत बेटी के जन्म के बाद सरकार सीधे खाते में प्रोत्साहन राशि भेजेगी, वहीं 18 साल तक अविवाहित रहने पर सरकार फिर से प्रोत्साहन राशि देगी.

ग्राम चौपाल कार्यक्रमों के जरिए महिला शक्ति को राज्य की शक्ति बनाने पर जोर दिया गया है. झारखंड जैसे समृद्ध राज्य की गरीबी को हमें दूर करना है. गांव-चौपाल के माध्यम से आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करना जरूरी है. पॉल्ट्री फेडरेशन सोसाइटी का गठन कर महिलाओं को जोड़ा जायेगा. इसके लिए फेडरेशन को चार लाख की राशि दी जायेगी. इससे महिलाओं के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा. आदिवासी विकास समिति में भी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए गांव के विकास की जिम्मेवारी सौंपी जा रही है. अब पांच लाख रुपये तक की योजनाओं को वे सर्वसम्मति से अपने गांव में लागू कर सकती हैं.

हमारे देश में महिलाओं का दर्जा हमेशा ऊंचा रहा है. वैदिक काल की विदूषी महिलाओं ने अपने ज्ञान, मेधा और कर्मचेतना से इस राष्ट्र को सींचने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी. हाल ही में नवरात्र और दीपावली का पर्व संपन्न हुआ. इन पर्वों में भी हमारी महिलाओं के यथोचित सम्मान, आह्वान और उनके सबल अस्तित्व का संदेश छुपा हुआ है. सशक्त महिलाएं पूरे समाज को एक सूत्र में बांध सकती हैं, विपत्तियों को साध सकती हैं और देश-समाज को अपनी संवेदनशीलता से नयी राह दिखा सकती हैं. हम मानते हैं कि वर्तमान समाज में महिला सशक्तीकरण महज एक नारा नहीं, बल्कि यह हमारा दायित्व है. महिलाओं के हर क्षेत्र में आगे आने और राष्ट्र के विकास में कंधा से कंधा मिलाकर काम करने में ही पूरे राष्ट्र का कल्याण निहित है. कई पितृसत्तात्मक परिवारों में अपेक्षाकृत महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, लेकिन हाल के वर्षों में हमारे समाज में महिला सशक्तीकरण की नयी चेतना उभरी है. इसके परिणामस्वरूप हमारे समाज में महिलाएं अब निर्णायक भूमिका में दिख रही हैं. यह परम संतोष का विषय है.

झारखंड जैसे राज्य में, खास कर आदिवासी समाज में महिलाओं को सबल करने और उनके परिवार में निर्णायक भूमिका निभाने के सारे अवसर मौजूद हैं. हमारे पुरखों ने महिलाओं को पुरुषों से कभी कमतर नहीं समझा. यही कारण है कि वे खेत से लेकर फैक्ट्री, कॉरपोरेट जगत से लेकर कारोबार की दुनिया में तेजी से जगह बना रही हैं. हमारी सरकार ने जब पहली बार दो वर्ष पूर्व आम बजट में जेंडर बजट का प्रावधान रखा था, तो उसके पीछे सोच यही थी कि राज्य के हर वर्ग की महिलाओं को सबल कर उनके हाथों में निर्णायक शक्ति दी जाये, ताकि राज्य की आधा आबादी अपने बूते खड़ी हो सके. हमने राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूली बच्चियों को साइकिल योजना, गरीब महिलाओं को धुएं से आजादी देने के लिए उज्ज्वला योजना, महिलाओं के नाम पर एक रुपये में जमीन की रजिस्ट्री, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास, नौकरीशुदा महिलाओं के बच्चों के लिए पालना घर, आर्थिक प्रोत्साहन के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा का लाइसेंस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ , शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने के लिए पुख्ता स्वास्थ्य योजना, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक जागरूकता अभियान जैसी योजनाएं चलायी हैं. ये सिर्फ योजनाएं ही नहीं हैं, बल्कि ये राज्य में युवा लड़कियों व महिलाओं के समग्र विकास के सूत्र हैं, क्योंकि इन योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है. इससे राज्यभर में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार देखा जा रहा है.

जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना सरकार का लक्ष्य है. वर्ष 2014 में राज्य मात्र 18 फीसदी खुले में शौच से मुक्त था. राज्य की सात हजार रानी मिस्त्री, जलसहिया व अन्य के सहयोग से शौचालय से स्वच्छता की ओर बढ़ते हुए चार साल में राज्य को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया.

राज्य में दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने के उद्देश्य से संखी मंडल की दीदियों को जोड़ा जा रहा है. सखी मंडल की दीदियां गाय पालन करें, इसके लिए सरकार 50 फीसदी अनुदान पर गाय उपलब्ध करा रही है.

हमने राज्य में गरीब एवं ग्रामीण परिवेश की बच्चियों के लिए उड़ान स्कॉलरशिप के माध्यम से पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया है. दूसरी ओर मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान के तहत गांव के घरों के बाहर नेमप्लेट पर बेटियों के नाम लिखे जाने की योजना पूरे राज्य में चल रही है. हम 14 से 24 साल की पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से पढ़ने और कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए तेजिस्वनी योजना चला रहे हैं. इसमें पढ़ाई या ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सरकार द्वारा तीन किश्तों में 10 हजार रुपये दिये जाते हैं. राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंडों में यह योजना चालू की गयी है. 1400 करोड़ रुपये की इस योजना के तहत 3400 महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराया जायेगा.

पिछले दिनों आयोजित ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर समिट में राज्य के किसानों के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया. बोकारो से आयी महिला किसान ने कहा था कि मुझे फख्र है कि मैं झारखंड की किसान हूं. हम सब तबीयत से किसान हैं. आज खुश होकर और आत्मविश्वास से लबरेज होकर लौट रही हूं. हम अपने पुरखों को उनका कल लौटाएंगे. उन्होंने हमें खेत दिये, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में उन पुरखों का सपना कहीं पीछे छूट गया था, लेकिन अब नहीं. इनकी बात से ऐसा लगता है कि अब गांव की आत्मा यानी खेती पुनर्जीवित हो रही है.

मेरा मानना है कि उपरोक्त सारे प्रयास ऐसे हैं, जो महिलाओं के स्वाभिमान को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं. हमारी बेटियां व महिलाएं कहीं से भी कमतर नहीं हैं. उन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और आत्मविश्वास के बूते कई सराहनीय और हैरतअंगेज काम कर दिखाये हैं. जरूरत सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित करने की है. हमारा सकंल्प है कि हम महिला सशक्तीकरण एवं विकास के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेंगे. महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान आये, इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है.

जन चौपाल में ग्रामीणों की सुनी फरियाद.

डेयरी विकास के लिए महिला को दी गाय (सांकेतिक).

आजीविका के लिए महिला समूहों को दी आर्थिक मदद.